वेदांत के शेयरधारकों ने उड़ीसा में नियमगिरी पर खुदाई के लिये प्रबंधकों को आड़े हाथ लिया

खान कम्पनी वेदांत के शेयर धारकों की सालाना बैठक में प्रदर्शनकारियों ने इसके प्रबंधकों पर मानव अधिकारों के कथित हनन और पर्यावरण के विरुद्ध अपराधों के आरोप लगाए। लन्दन में इस बैठक एक दौरान जहां सभागृह के बाहर प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे, वहीं सभागृह के अन्दर कम्पनी के बड़े अफसर, शेयरधारकों, मशहूर कार्यकर्ताओं, और समाज सेवी संगठनों के हमले झेल रहे थे।

बैठक के दौरान रौलिंग स्टोन सितारे माईक जैगर की पूर्व पत्नी बिआंका जैगर ने डोंगरिया कौंध आदिवासियों का मार्मिक सन्देश पढ़ते हुए नियमगिरी पहाड़ों पर बॉक्साईट की खुदाई समेत उड़ीसा में यह प्रोजेक्ट बन्द करने की अपील सन्देश में कहा गया था- पीढ़ियों से हम नियमागिरि के सहारे अपना जीवनयापन करते आ रहे हैं, लेकिन आप उसे नष्ट करने जा रहे हैं।

वेदांत के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल और सी ई ओ एम एस मेहता ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि इस परियोजना से भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक में सम्पन्नता आएगी। मेहता ने कहा कि बच्चों में कुपोषण की दर 50 फीसदी से भी अधिक है और लोग शहरों में जाकर काम ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे हैं । हमारा प्रोजेक्ट से उन्हें रोजगार और सम्पन्नता देगा।

बैठक के बीच श्रोताओं में से एक व्यक्ति द्वारा मध्य भारत में वेदांत की एक परियोजना में चिमनी गिरने से मरे 41 लोगों के लिए दो मिनट का मौन रखने को अध्यक्ष अनिल अग्रवाल राजी हुए। बैठक में मौजूद एक कम्पनी ने प्रबन्धकों द्वारा पेश प्रस्तावों के विरुद्ध मतदान किया जबकि ब्रिटिश संसद के अध्यक्ष मार्टिन हॉर्वुड ने वेदांत से निवेशकों को पूरी जानकारी न देने के लिए आड़े हाथो लिया (गार्जियन, यू के)

14 राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं पर सीबीआई की पैनी नज़र

नई दिल्ली, 29 जुलाई (टाईम्स ऑफ इंडिया)। राष्ट्रमंडल खेलों की परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की गंध आने से सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसिया केन्द्रीय सतर्कता आयोग(सी वी सी) और केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरो, सीबीआई उन परियोजनाओं के अमल पर बाज सी पैनी नज़ रख रही है, जिनके खर्च अनुमानित लागत को पार कर चुके है सी वी से ने जहां इस बात की पुष्टि की है कि वह परियोजनाओं की जांच कर रही है।

सीबीआई और नियंत्रक और महा लेखापरेक्षक (कैग) के सूत्रों ने कहा है कि शिकायतों के ढेर को देखते हुए राष्ट्रमंडल खेलों, दिल्ली सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण के खर्च में उनकी दिलचस्पी बढ़ती ही जा रही है। इन सूत्रों ने कहा कि फिलहाल ऐसे 14 परियोजनाएं है जिन पर नजर रखी जा रही है लेकिन शिकायतों के बढ़ते स्तर को देखते हुए इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। सी वी सी की ही तरह सीबीआई को भी विभिन्न स्त्रोतों से हजारों करोड़ों रूपयों के ठेके देने में अनियमितताओं की शिकायतें मिली है। शिकायत करने वालों में संबंधित समूह और अन्याय की शिकायतें करने वाले पक्ष शामिल है।

खेलों के लिए हो रही परियोजनाओं के अमल के ठेके देने में भ्रष्टाचार और पक्षपात की शिकायतें आम है- इनमें से कई तो समय अभाव का बहाना बनाते हुए निविदाओं के नियमों का उल्लंघन करते हुए बांटे गए है। भ्रष्टाचार की जांच की संभावना कांग्रेस में बढ़ती इस चिंता के बीच व्यक्त की जा रही है कि खेल सरकार के लिए शर्मिन्दगी का सामान बन सकते है। यह आशंका कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने प्रेस के साथ अपनी नियमित बातचीत के दौरान व्यक्त की अनियमितताओं और घटिया कामों की खबरों से संबंधित सवालों की बौछार का सामना करते हुए उन्होंने कहा कि जो सवाल उठाए जा रहे है, वह प्रासंगिक है। हालांकि तिवारी ने खेलों में हो रहे खर्च को पैसो की पूरी बर्बादी के मणिशंकर अय्यर के बयान से कांग्रेस को दूर करते हुए कहा अय्यर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं। जबकि खेलों का सफल आयोजन राष्ट्रहित का मुद्दा उन्होने कहा-'चूंकि हमने अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी ली है, हमें यह तय करने के ज़रूरत है कि यह तेजी से पूरा हो। अगर खेल कामयाब नहीं रहे तो यह किसी एक की बदनामी नही होगीं, बल्कि हमारे देश के सम्मान को बट्टा लगेगा।' तिवारी ने यह भी कहा कि खेलों के बाद शायद इसके पोस्ट्मार्टम के जरूरत पड़े।

नाम न लिखे जाने की शर्त पर कांग्रेस नेता कहते है कि खेलों से पार्टी को नुकसान हो सकता है खेलों के नाम पर चल रही लूट की खौफनाक घटनाओं पर टिप्पणी करते ने कहा- 'अक्षमता और घटिया काम की तमाम रिपोर्टो एक बीच हम हाथ पर हाथ बान्धे बैठे है। यह सीबीआई को अगले दो सालों तक व्यस्त रखने के लिए काफी है।' एक वरिष्ठ मंत्री बताते है कि आयोजन समिति के मुखिया सुरेश कलमाड़ी ने एशियाई खेलों के लिए सरकार की निविदाएं कैसे हासिल की थी उन्होंने कहा-'खुशिकस्मती से हम हार गए, कम से कम एक बड़ी मुसीबत से बच गए।' वरिष्ठ नेताओं के बीच लड़ाई ने पार्टी के अनेक लोगों को हताश कर दिया है। कांग्रेस के मुखपत्र संदेश के सम्पादक अनिल शास्त्री ने ट्वीट किया है-'राष्ट्रमंडल खेल सबके लिए टिप्पणियां करने का सामान बन गए हैं। तैयारियों के स्तर पर ही फ्री स्टाईल कुश्ती देखने को मिल रही है। यह निंदनीय है 'जब उनसे

नई दिल्ली के एक स्कूल में पूर्व ओलंपिक चैंपियन केली होम्स एक छात्रा के साथ फुट बाल खेलते हुए। वे अभी कामनवेल्थ गेम की चल रही तैयारियों का जायजा लेने आई टीम की एक सदस्य हैं।

उनके संदेश का अर्थ पूछा गया उन्होंने कहा कि मामले के निपटारे के लिए सर्वोच्च स्तर पर दखल की जरूरत है 'खेलने वाले देश के रूप में भारत की छवि दांव पर लगी है' सी वे सी में मुख्य तकनीकी निरीक्षक ने निविदा दस्तावेजों पर गौर करने के बाद सैकड़ो करोड़ो खर्च करने वाली, अमल के लिए जिम्मेदार तमाम एजेंसियो पीडब्लूडी, डीडीए, एमसीडी, सीपीडब्लूडी को भेजे जाने वाले विशिष्ट सवाल तैयार कर लिए है।

इन एजेंसियो को कैग के सामने भी अपने हाथ में लिया जाना था जिसके तहत-

1 ला चरण पूरी योजना पेश कर दी जानी चाहिए थी(जनवरी 2004- मयी 2006)

2रा चरण- ढांचा खदा करना (मई2006- मई 2008)

3 रा चरण पूरी हो चुकी योजनाओं को मई 2009 से सौंपना शुरू कर देना था। अगस्त 2009 में कैग की ऑडित रिपोर्ट मे कहा गयाप्पहले चरण की समयावधी में और दूसरे चरण के अधिकांश समय मे चरण बद्ध क्रियांवयन नजर नही आया।

द्वारा खर्च की गई राशि उचित ठहरनी पड़ेगी। 2003 में जब खेल भारत में करना तय किया गया था, उनकी अनुमानित लागत 635 करोड़ लगाई गई थी खर्च यह रकम उस समय बहुत छोटी इसलिए लगी क्योंकि यह समझा गया कि इससे देश में 840 करोड़ रूपए की आय होगी जिसके कारण देश को 205 करोड़ रूपयों की अतिरिक्त आय होगी। हालांकि इस लागत को अगस्त 2007 में सुधार कर 767 करोड़ और 2008 में 1, 780 करोड़ रूपए कर दी गई यह लागत बढ़ते ही जा रही है और आयोजको द्वारा समय के कमी की बात करने के कारण लागत बढ़ते ही जा रही है अंतरराष्ट्रीय मार्ग-निर्देश के मुताबिक राष्ट्रमंडल खेलों की सारी परियोजनाएं मई 2009 तक पूरी कर ली जानी चाहिए थी जबकि पहला स्टेडियम परीक्षण के लिए कुछ ही दिनों पहले सौंपा गया है। 2003 में नई दिल्ली में इन खेलों के घोषणा के बाद चरणबद्ध काम

गणित का चौराहा - 1351

7	+	5	-	3	9
-	■	×	■	+	
6	×	1	-	4	2
+	■	+	■	/	
8	+	9	+	2	19
9		14		5	

अंक जाल-1431 का हल

	12	13	35	30		12	16	22	
24	2	6	7	9		7	2	5	14
20	5	4	9	2		5	8	7	20
25	5	3	8	2	7		4	7	11
			5	7	8	9	2	3	34
35	8	5	6	7	3	6			
7	2	5		3	4	7	8	8	30
19	5	8	6		4	6	8	7	25
14	3	5	6		7	3	2	7	19
	18	23	12		33	31	18	22	

सुडोकू- 1621 का हल (E)

2	6	9	1	7	8	4	5	3
8	5	3	4	2	6	7	1	9
7	4	1	5	3	9	8	2	6
6	1	4	8	5	2	9	3	7
5	7	8	9	1	3	6	4	2
3	9	2	6	4	7	1	8	5
4	3	6	7	8	5	2	9	1
1	2	7	3	9	4	5	6	8
9	8	5	2	6	1	3	7	4

मिनी सुडोकू-492 का हल

1	4	3	6	5	2
5	6	2	1	3	4
6	1	5	2	4	3
2	3	4	5	6	1
3	2	6	4	1	5
4	5	1	3	2	6

छत्तीसगढ़ शब्द पहेली क्रमांक-1591 का सही उत्तर

अ	ब्दु	ल	■	■	■	■	■	■
र	■	ज्जा	■	■	■	■	■	■
मा	ह	■	■	■	■	रो	ज	■
न	सी	ब	■	■	■	म	ज	मा
■	ना	र	की	य	■	गा	ना	■
अ	■	सा	■	ती	हा	र	■	■
प	र	त	■	■	म	मी	■	■
ने	जा	■	ग	■	■	अ	■	घ
आ	मं	त्र	ण	■	■	ल	ब	रा
प	द	■	ना	क	र	ग	ड़	ना

100 गांव विस्थापित करके, देश में चीतों को दोबारा बसाने की योजना

नई दिल्ली, 29 जुलाई (टाईम्स इंडिया)। केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने देश में तीन स्थानों पर चीता को दोबारा लाने की योजना को बुधवार को हरी झंडी दे दी। इस महत्वाकान्क्षी परियोजना के पहले ही साल मे 300 करोड रुपयो का खर्च होगा जबकि इसके कारण करीब 100 गांवों में रहने वाली आबादी विस्थापित होगी।

रमेश ने कहा कि उनका मंत्रालय पूर्व पर्यावरण सचिव और भारतीय वन्य जीवन ट्रस्ट के ट्रस्टी एम के रणजीत सिन्ह, चीता पर किताब के लेखक दिव्यभानु सिन्ह और भारतीय वन्य जीवन संस्थान के वाय वी जाला के अफ्रीकी या इरानी चीते आयात करने के प्रस्ताव से सहमत है। यह चीते मध्यप्रदेश एक कुनो-पालपुर वन्यजीवन अभ्यारण्य और नौरादेहे वन्य जेवन अभ्यारण्य और राजस्थान के जैसलमेर इलाके के शाहगढ़ इलाके में रखे जाने का प्रस्ताव है योजना के मुताबिक इन चीतों के रहने की जगह विकसित करने के लिए 5, 600 एकड् सूखी जमीन प्राकृतिक स्थल में विकसित की जाएगी। जिसके कारण इस पर रहने वाली आबादी का विस्थापन हो जाएगा। जैसलमेर के करीब योजना स्थल पर मौसमी खानाबदोशों के 80 गांव है। इसके पहले कुनो- पालपुर मे गुजरात के गिर सिन्हो के लिय जगह देने के लिए 23 गांव वहां से हटाने पड़े थे, अब तीन और गांव हटाने पड़ेंगे नौराडीह मे वन अधिकार अधिनियम क दिशा निर्देशो क पालन के लिये 23 गांव दोबारा बसाने पड़ेंगे।

वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि वह मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को शीघ्र पत्र लिख कर उन्हें प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलाएंगे चीते या पश्चिम एशियाई देशों या नाम्नीबिया या दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे , जहां अफ्रीकी चीतों का प्रजनन किया जाता है। हालांकि तेहरान से भी सम्पर्क किया जाएगा, तेहरान यह जानवर देने के पक्ष में नहीं है क्योंकि उसके यहां भी यह गिनी चुने संख्या में ही बचा है।

रणजीत सिंह ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात भारत की मांग मान लेगा। प्रस्ताव के मुताबिक शुरुआत मे हर जगह 6 चीत रखे जाएंगे झाला ने कहा-'पूरी योजना अमल मे आने मे 10 से 15 साल लग सकते है।' मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट मे कहा गया है कि एक दशक मे नौरादेही में सीमित क्षेत्र में 50 चीते हो सकते है, जबकि इलाके में रहने के लिए कुदरती जगह पाकर आसपास के जंगलों से 20 चीते और आ सकते है इसी तरह इतने ही समय मे कुनो- पालपुर में 32 चीते और उसके आसपास के जंगलो और घास के मैदानों में 38 चीते आराम से रह सकते है रिपोर्ट के मुताबिक शाहगढ़ को 140 किलोमीटर लंबी बाद से सुरक्षित करने के ज़रूरत है, जिसके बाद वहां 40 जानवर पनप सकते हैं। रमेश ने कहा कि यह परियोजना इस लिहाज से अहम है कि चीता ही एक ऐसा जानवर है जो पिछले 1000 सालों में देश से लुप्त हो गया है इसके साथ ही जानवार अपने नए घर में घास के मैदान और सूखे मैदान संरक्षित करने में मददगार होगा।

रणजीत सिंह ने कहा-'घास के मैदांनो को बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि इन इलाको से इंसान का दबाव कम कर दिया जाए।' झाला ने कहा-'सभी विकसित देशो मे जानवरो को दोबारा बसाने के कानून है, और भारत इसका अपवाद नही है।'

पेज 6 से आगे

डीजल में मिलाओ पानी

उससे निकलने वाले धुएं में कालिख और नाइट्रस ऑक्साइड के बहुत अधिक अनुपात का निवारण। लेकिन क्योंकि पानी और डीजल का मेल आसानी से होता नहीं, इसलिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरों को फ़िलहाल ऐसे विकल्प अपनाने पड़ते हैं, जो मोटर में दहन क्रिया के समय नपी-तुली मात्रा में पानी के छींटे डालें। इस प्रकार के इंजेक्टिंग सिस्टम बहुत महंगे पड़ते हैं। इसलिए उनका अधिक प्रचलन नहीं हो पा रहा है।राइनहार्ड स्ट्रे डीज़ल और पानी का ऐसा मिश्रण तैयार करने में लगे हैं कि मोटर की बनावट में कोई परिवर्तन करना ही न पड़े।

वह कहते हैं, 'यह एक बिलकुल सामान्य डीजल मोटर है, कोई हेरफेर नहीं किया गया है। सिर्फ़ एक छोटा सा पिस्टन अलग से बैठाया गया है, जो मोटर में खपने वाले डीजल के अनुपात में पानी पंप करता है। यह पानी इमल्सिफ़ायर कहलाने वाले उपकरण में डीजल के साथ मिलाया जाता है। दोनों के मिश्रण से जो इमल्शन बनता है, उसे मोटर के दहन कक्ष में इंजेक्ट किया जाता है। वही कालिख और नाइट्रस ऑक्साइड को घटाता है। राइनहार्ड स्ट्रे की परीक्षण कार की डिक्की में पानी की अलग टंकी है। अतिरिक्त पिस्टन वाला उपकरण उसी से पानी लेता है।

इमल्सिफ़ायर में डीजल और पानी का अभी केवल ऐसा इमल्शन बनता है, जो बहुत टिकाऊ नहीं है। स्ट्रे ऐसा इमल्शन चाहते हैं, जिसे डीजल के बीच पानी की अतिसूक्ष्म बूंदों वाला माइक्रो इमल्शन कहा जा सके। इसे वे तथाकथित टेंसीडों की सहायता से प्राप्त करना चाहते हैं। टेंसीड ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं, जो उदाहरण के लिए, साबुन या कपड़ा धोने के पाउडर में मिले होते हैं और पानी का तलतनाव कम करने में सहायक बनते हैं। वह कहते हैं, टेंसीड और डीज़ल का मिश्रण एक तरह से सूखे स्पंज के समान होगा, जिसे बस पानी का इंतज़ार है। जैसे ही उसे पानी मिलेगा, उसके टेंसीड अणु पानी को तुरंत घुलनशील बना देंगे।डीजल की तरह ही टेंसीड भी मूल रूप से कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं और मोटर में पूरी तरह जल कर भस्म हो सकते हैं। उनके मुताबिक, च्अब तक के परीक्षणों में हमने देखा कि पानी की मात्रा बढ़ने से हम पानी के 20-30 प्रतिशत तक अनुपात की बात कर रहे हैं। मोटर से निकलने वाले धुएं में कालिख की मात्रा घटती जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा भी बिना किसी तकनीकी तामझाम या मोटर की बनावट में बिना किसी परिवर्तन के 10, 20 या 30 प्रतिशत तक घटाई जा सकती है। (डॉयचे वैले)

गुजरात में मुठभेड़ का सच

क्या अब समय आ गया है कि स्वामी अग्निवेश आंध्र पुलिस को हत्या में शरीक ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करें ? साथ ही यह दलील पेश करें कि यह हत्या आंध्र पुलिस के संज्ञान में है और इसके बाद वह इन सवालों पर मौन साध लेगी।

सरकार का दुश्मन कौन है ? ये सवाल पूछना ज्यादा आसान है बनिस्बत कि इसके जवाब ढूंढना। कसाब और उस जैसे हजारों अन्य घुसपैठी आतंकियों के मामले में तो भ्रम की कोई स्थिति नहीं रहती। लेकिन जब श्रेणियां बदल जाती हैं तो उच्चतम न्यायालय के लिए भी सच्चाई धुंधला जाती है। अदालत का यह कथन साहसभरा है कि सोहराबुद्दीन जैसा हत्यारा किसी खूनी दस्ते का सामना नहीं कर सकता। तो क्या कोर्ट के विचार में ये है कि आजाद को बिना मुकदमा चलाए मार दिया जाना चाहिए था, क्योंकि आंध्रप्रदेश और दिल्ली में बैठे हुक्मरानों ने यह तय किया था ?

सुप्रीम कोर्ट कोई राजनीतिक दल नहीं है. वह व्यावहारिक जरूरतों के लिए अपने उसूलों में रद्दोबदल नहीं कर सकती। *(लेखक द संडे गार्जियन के संपादक हैं)* (www.raviwar.com)

4 करोड़ के ठेके का 8 करोड़ भुगतान !

पहले पेज से आगे

श्री पटेल ने कहा कि ब्याज समेत भुगतान करने के आदेश के खिलाफ अपील की जानी चाहिए थी। इस तरह बगैर काम किए कोई भी ठेकेदार पैसा ले सकता है। मंत्री ने बताया कि मामले में शासन के विधि विभाग से राय ली गई थी। विभाग ने सुझाव दिया था कि अपील करने के लिए उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है तो संभव है कि अदालत 16 करोड़ रूपए भुगतान करने का आदेश दे दे। लिहाजा इस मामले में अपील करने का विचार छोड़ दिया गया।

कांग्रेस विधायक ने कहा कि एक तरफ सरकार हसदेव बांगों के कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है, वहीं इस मामले में केवल दो दिन के भीतर ठेकेदार को दोगुना भुगतान कर दिया गया। उनका कहना था कि सरकार ने इस मामले में महाधिवक्ता से भी राय नहीं ली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी सदन की कमेटी से जांच करानी चाहिए।

मंत्री ने सदन की कमेटी से जांच कराने से इंकार करते हुए कहा कि यह कमेटी के जांच का विषय नहीं है। वे इस मामले की तकनीकी परीक्षक से जांच करवाएंगे। श्री पटेल ने कहा कि तकनीकी परीक्षक ईएनसी के अधीन काम करता है और इस मामले में उससे बड़े अधिकारी संलिप्त हो सकते हैं ऐसे में तकनीकी परीक्षक से जांच कराने का कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के बाहर के ठेकेदार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। ऐसे में यह प्रवृत्ति बन जाएगी और बगैर काम हुए भुगतान होता रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और नेता प्रतिपक्ष रविन्द्र चौबे ने भी इस मामले की सदन की कमेटी से जांच कराने का आग्रह करते हुए कहा कि दक्षिण भारत की कंपनियां यहां पर लूटने आई हैं। मंत्री आखिर तक इस मामले की सदन की कमेटी से जांच कराने से इंकार करते रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे मामले को प्रश्न एवं संदर्भ समिति से जांच कराने की घोषणा की।

अपने सदस्यों की संपत्ति की सूचना देने में डेढ़ बरस से कतरा रहा सूचना आयोग

नई दिल्ली, 29 जुलाई (टाईम्स ऑफ इंडिया)। पूरे देश को पारदर्शिता का उपदेश देने वाले केन्द्रीय सूचना आयोग को अपनी ही सीख पर अमल करने में मुश्किल हो रही है। सूचना आयुक्तों की सम्पत्ति के ब्यौरे के बारे में एक सूचना अधिकार याचिका पर उसे 18 महीने हो चुके हैं। लेकिन केन्द्रीय सूचना आयुक्त इस बिना पर यह सूचना दबाए बैठे हैं कि उन्होंने इस पर निर्वाचान आयोग की राय मांगी है। 9 में से एक सूचना आयुक्त शैलेष गांधी ने अपनी सम्पत्ति की जानकारी सार्वजनिक कर दी है।

सोमवार को पारित एक आदेश में मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने कहा कि चूंकि गांधी ने अपनी जायदाद के ब्यौरे सार्वजनिक करने की मंशा खुद जाहिर की है, इसलिए उनकी अनुमति लेने के बाद यह सूचना सार्वजनिक की जा सकती है। हबीबुल्ला ने कहा कि चूंकि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत गांधी की पहचान तृतीय पक्ष के रूप में की गई, उनकी स्वीकृति लेनी जरूरी है। शेष के लिए चुनाव आयोग की सलाह आयोग ने मांगी है। यह निर्देश नवंबर 2008 में पुने के विहार ध्रुव द्वारा सम्पत्ति की घोषणा सम्बन्धी सूचना आधिकार याचिका दायर की। सीपीआईओ के मुख्य सूचना अधिकारी तरुण कुमार ने बताया कि आयुक्तों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। लेकिन मुख्य सूचना आयोग द्वारा ऐसी कोई सूचना इकट्ठी नहीं रखी जाती है इससे नाराज़ हो कर ध्रुव ने ऐसी सूचना जाहिर होना व्यापक जनहित में होने की बात करते हुए एक अपील दायर की।

इन दलीलों का विरोध करते हुए ध्रुव ने एक दूसरी अपील दायर की इसके जवाब में कुमार ने कहा कि केन्द्रीय सूचना आयोग ने तो चुनाव आयोग से तीन बार सलाह मांगी है। लेकिन अभी तक उसे कोई जवाब नहीं मिला है। हबीबुल्ला ने अपने कार्यालय को जरूरी राय मंगवाने के मामले में तेजी लाने को कहा।सम्पत्ति की घोषणा में हो रही देरी आयोग के भीतर मतभेद का संकेत है जो कि विभिन्न आयुक्तों के आदेशों से भी जाहिर है। सूचना आयुक्त शैलेष गांधी ने कई बार अपने कई आदेशों में कहा है कि सरकारी अधिकारियों को अपनी सम्पत्ति घोषणा करनी चाहिए।

अन्य सूचना आयुक्त ऐसा करने में हिचकते रहे हैं। सच तो यह है कि इनमें से ज्यादा को यह लगता है कि यह उनकी निजी गोपनीयता में दखल है। विडम्बना यह है कि केन्द्रीय सूचना आयोग ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और निर्वाचित प्रतिनिधियों को जन अधिकारियों में शुमार किया है।

Name, Fame and Game-1538 Solution

अगर आप कुछ नाम ढूंढ न पाए हों तो यहां दिए गए उत्तरों की मदद लें। नामों को आड़ी और खड़ी कतारों के नंबर व उनकी दिशा के आधार पर ढूंढें

(Over,Down,Direction)

BADEGHARKIBETI(14,15,NW)
BILLOOBADSHAH(2,1,SE)
BIWIHOTOAISI(1,16,E)
CHAALBAAZ(12,9,NW)
DARIYADIL(3,13,E)
DILHAIBETAAB(12,2,SW)
DILTERAAASHIQ(1,23,E)
DOST(17,19,N)
GAIRKAANOONI(12,15,NW)
GANGATEREDESHMEIN(1,21,E)
GHARGHARKIKAHANI(13,1,S)
GHARHOTOAISA(12,22,W)
HUMBHIINSAANHAIN(1,1,SE)
KALABAZAAR(16,5,S)
KANOONAPNAAPNA(15,14,N)
KASAM(14,23,NW)
KHOONBHARIMAANG(15,17,W)
MAJBOOR(1,6,SE)
NISHANEBAAZI(18,21,N)
PARAYAGHAR(3,1,SE)
PYAARMOHABBAT(17,1,S)
SHAHENSHAH(10,14,W)
SHERNI(18,1,S)
SHOORVEER(14,9,N)
SHUKRIYAA(1,11,NE)
SIKKA(17,20,SW)
VARDI(18,24,W)

फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी की पत्नी कार्ला ब्रूनी फिर से अभिनय की ओर लौट आई हैं। ब्रूनी का कहना है कि फिल्म 'मिडनाइट इन पेरिस' के एक दृश्य की शूटिंग के लिए उन्हें 32 रिटेक देने पड़े। यह फिल्म हॉलीवुड के मशहूर निर्माता- निर्देशक वूडी एलन बना रहे हैं। वेबसाइट 'डिजिटलस्पाइ डॉट को डॉट यूके' के मुताबिक ब्रूनी ने मंगलवार को पेरिस की एक इमारत के निकट एक सड़क पर देर रात अभिनेता ओवेन विल्सन के साथ शूटिंग की। शूटिंग देखने राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी भी आए थे। गौरतलब है कि 'मिडनाइट पेरिस' में एड्रियन ब्राडी और रचेल मैक्एडम्म भी काम कर रहे हैं और यह फिल्म वर्ष 2011 में प्रदर्शित होगी।

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग रायपुर

प्रारूप अधिसूचना धारा 4 (1) भू-अर्जन अधिनियम 1984

क्रं./भू-अर्जन/प्र.क्रं.2/ए82/वर्ष 2009-10 **रायपुर, दिनांक- 7.7.10**

चूंकि राज्य शासन के यह प्रतीत होता है कि नीचे दिए गए अनुसूची 'अ' खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की उनकी सामने अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अत: भू-अर्जन अधिनियम 1984 (क्र.1 सन् 1894) की धारा 4 (1) के तहत एतद् द्वारा यह लोक सूचना जारी की जाती है। तदानुसार उक्त अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को अधिनियम की धारा 4 (2) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

अनुसूची 'अ'

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोग
	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
1	2	3	4	5	6
रायपुर	बलौदाबाजार	डोंगरा प.ह.नं. 29	2.362 हे.	कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध संभाग क्रमांक-2 बलौदाबाजार	लवन शाखा नहर निर्माण हेतु

छत्तीसगढ़ के राज्याल के नाम से तथा आदेशानुसार

(संजय गर्ग)
कलेक्टर एवं पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग, रायपुर

जी-13351